THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): No such news-item has appeared in the Hindustan Tiems dated the 1st January, 1999 as stated by the Hon'ble Memebr of Parliament in his question, However, such a news-item was published in the Hindustan Times (Delhi Edition) on 1st February, 1999. The Government's atention has bene drawn to the said news-item on the proposed Amendment of Land Acquisition Act, 1894. It is not, however, a fact that the Government has started re-thinking on rehabilitation aspect on the basis of such write-ups in news-items. In the draft Land Acuquisiton (Amendment) Bill, 1988, there were necessary provision in the various clauses of the proposed bill to provide necessary legal powers to the Competent Authorities for effective implementation of the National Policy on Resettlement and Rehabilitation as well as existing State legislations on the subject for the time being in vogue in several States.

Model villages in Andhra Pradesh

298. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of villages in Andhra Pradesh developed as model villages under the Centrally sponsored Rural Sanitation Programme;

(b) the amount earmarked for this purpose during the year, 1998-99.

(c) whether Government of Andhra Pradesh have sent specific Project to Central Government for approval and release of funds under the Programme;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the likely time frame for clearance of the project if any, under consideration by Central Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL); (a) to (e) Andhra Pradesh has so far sent eighteen proposals for the development of model villages under the Centrally Sponsored Rural Sanitation Programme (CRSP). As against the total cost of the Projects amounting to Rs. 108.416 lakh, Rs. 68.397 lakh have so far been released. of which State Government has reported as expenditure of Rs. 20.580 lakh. Subsequent instalments could not be released as the utilisation was not up to the mark. No proposal has been received from the State Government during 1998-99.

New Proposal to Modernise NTC Mills

299. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a new proposal to rationalise and modernise the National Textile Corporation (NTC) mills has been under consideration of Government; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) On the basis of a unit-wise viability study made by NTC, Government is considering a revised turn around strategy for the viable subsidiaries of NTC alongwith the viable mills under them, keeping in view the BIFR norm of the net worth of these mills turning positive, within the period prescribed by BIFR. The interest of the workers will be kept in view in the revival plan.

विभिन्न क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष का वितरण

300. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री राज मोहिन्द्र सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के वस्त्र उद्योगों में उपयोग होने वाली तकनीक का विकास करके उत्पादन बढ़ाने के

लिए 25,000 करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कोष से हथकरघा उद्योग, बिजली करघा उद्योग तथा मिल उद्योग क्षेत्र में तकनीक के विकास के लिए भागीदारी का कितना-कितना अंश निर्धारित किया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अंश के निर्धारण हेतु क्या-क्या मानक तय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत वस्त्र और पटसन उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों के एकक ब्याज की पात्र दर पर नोडिए एजेंसियों से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। ब्याज की दर में अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति संबंधित नोडिए एजेंसियों को सरकार द्वारा की जाएगी। हथकरघा, विद्युतकरघा अथवा मिल क्षेत्र जैसे वस्त्र उद्योग के किसी विशेष क्षेत्र के लिए कोई अंश निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उद्योग के विकास एवं विस्तार हेतु योजना

301. श्री कपिल सिब्बल:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के वस्त्र उद्योग के विकास व विस्तार हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में वस्त्र-उद्योगों में उपयोग करने हेतु नयी तकनीके के शोध एवं अन्वेषण हेतु कोई कार्य-योजा भी तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा): (क) से (ग) इस समय 8 वस्त्र अनुसंधान संघ कार्य कर रहे हैं जिनका वित्तपोषण संयुक्त रूप से भारत सरकार, राज्य सरकारों और उद्योग द्वारा किया जाता है। ये वस्त्र अनुसंधान संघ सामान्यतः अनुसंधान व विकास से संबंधित क्रियाकलाप करते है, परीक्षण सहित अनुसंधान व विकास पर आधारित सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा भी प्रदान करते हैं। ये नवीन कार्य भी करते हैं तथा वस्त्र प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर उद्योग को परामर्शी सेवाएं भी देते हैं जिनमें शामिल है — मानव संसाधन विकास, वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकीय कार्य निष्पादन और लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिकता प्रक्रिया का प्रयोग। अनुसंधान व सेवाओं का उद्देश्य लागत को कम करने के साथ-साथ फैशिकों की गुणवत्ता और टिकाऊपन में सुधार लाना, प्रदूषण को कम करना, ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट का उपयोग तथा नई प्रौद्योगिक को अपनाना अथवा मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार लाना है। सरकार ने वस्त्र उन्नयन निधि योजना की स्थापना का अनुमोदन किया है। जिस के अन्तर्गत पात्र वस्त्र तथा पटसन इकाइयों को ब्याज की लागू दर पर ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना के अन्तर्गत 5% तक ब्याज का ब्याज बिन्दु का वस्त्र मंत्रालय द्वारा ऋण नोडिए एजेंसियों (आई, डी, बी आई, एस आई डी बी आई, तथा आई एफ सीआई) को प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

सूत के उत्पादन में गिरावट

302. श्री नरेन्द्र मोहन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सूत के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) देश से हर वर्ष कितने रुपयों का सूत निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या सूत के इस निर्यात में भारत विदेशों से प्रतिद्वंद्विता में ठहर पा रहा है अथवा उसके समक्ष कोई नयी समस्याएं आयी हैं; और

(घ) देश में सूत वाली वर्तमान मिलों की आर्थिक और प्रौद्योगिकीय स्थिति क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी नहीं सूती यार्न के उत्पादन आंकड़े विगत पांच वर्षों के निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	(मिलियन कि०ग्रा० में) उत्पादन
1994-95	1695
1995-96	1894
1996-97	2148
1997-98	2213
1998-99(क)	2045